

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Tuesday, 21 Jan, 2025

Edition: International Table of Contents

Page 04 Syllabus : GS 3 : भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि	सरकार ने आंशिक रूप से प्रतिबंध हटाया, दस लाख टन चीनी के निर्यात को मंजूरी दी
Page 05 Syllabus : GS 2 : भारतीय राजनीति	बिरला ने पार्टियों से सदस्यों के लिए आंतरिक संहिता बनाने का आग्रह किया
Page 06 Syllabus : प्रारंभिक तथ्य	अध्ययन में 268 जनजातियों को वर्गीकृत किया गया, 179 समुदायों को एससी, एसटी और ओबीसी सूची में शामिल करने पर विचार किया गया
Page 13 Syllabus : GS 2 : शासन	बीओजे 17 वर्षों में उच्चतम दरों को बढ़ाने के लिए तैयार
समाचार में	डब्ल्यूईएफ वार्षिक बैठक
Page 08 : संपादकीय विश्लेषण: Syllabus : GS 2 : शासन	यूजीसी के मसौदा विनियमन में गंभीर संवैधानिक मुद्दे हैं

केंद्र सरकार ने चीनी निर्यात प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटा दिया है, जिससे 2024-25 सत्र में दस लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति मिल गई है।

- ➔ इस कदम का उद्देश्य मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना, किसानों और श्रमिकों को लाभ पहुंचाना और अधिशेष स्टॉक को संबोधित करके चीनी मिलों के लिए तरलता को बढ़ावा देना है।

Govt. lifts ban partially, gives nod for export of million tonnes of sugar

The Hindu Bureau

NEW DELHI/COIMBATORE

The Union government on Monday lifted the ban on sugar exports partially, allowing industries to export one million tonnes in the 2024-25 season ending in September.

Union Food Minister Pralhad Joshi said the move would ensure price stability, benefit five crore farmer families and five lakh workers, and strengthen the sugar sector.

The export ban came into effect in October 2023 to regulate domestic prices.

The Food Ministry said the decision will ensure timely payments to farmers.

The move is expected to boost liquidity for sugar mills and balance sugar availability and prices for farmers. The Food Ministry's order allows the mill-



The export ban came into effect in October 2023 to regulate domestic prices. GETTY IMAGES

ers to export all grades of sugar within allocated quantities. They can export sugar either directly or through traders until September 30.

The Indian Sugar and Bio-Energy Manufacturers Association welcomed the decision, saying it will address the issue of surplus sugar stocks.

This timely decision will significantly aid sugar mills by enhancing financial liquidity, the ISMA said in a statement.

संभावित लाभ:

Daily News Analysis

- मूल्य स्थिरता: इस निर्णय का उद्देश्य नियंत्रित निर्यात की अनुमति देकर घरेलू चीनी की कीमतों को स्थिर करना है, ताकि अधिशेष स्टॉक के कारण कीमतों में गिरावट को रोका जा सके।
- किसानों के लिए सहायता: निर्यात को सक्षम करके, चीनी मिलों के पास बेहतर तरलता होगी, जिससे गन्ना उत्पादन में शामिल पाँच करोड़ किसान परिवारों को समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा।
- चीनी मिलों को बढ़ावा: निर्यात भत्ता अधिशेष स्टॉक को साफ करके, नकदी प्रवाह में सुधार करके और उनकी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाकर चीनी मिलों की मदद करता है।
- रोजगार को बढ़ावा: इस कदम से चीनी उद्योग में लगभग पाँच लाख श्रमिकों को लाभ होने की उम्मीद है, जिससे नौकरी की सुरक्षा में योगदान मिलेगा।
- भारत के चीनी क्षेत्र को बढ़ावा: यह निर्णय समग्र बाजार स्थिरता में सुधार करके और इसकी विकास क्षमता सुनिश्चित करके चीनी क्षेत्र को मजबूत करता है।

चुनौतियाँ:

- घरेलू कमी का जोखिम: यदि सावधानीपूर्वक निगरानी नहीं की जाती है, तो चीनी निर्यात करने से घरेलू बाजार में कमी हो सकती है, जिससे कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है।
- अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिशीलता: वैश्विक चीनी बाजार की अस्थिरता निर्यात के लाभों को प्रभावित कर सकती है, खासकर अगर मांग में उतार-चढ़ाव होता है या अंतरराष्ट्रीय कीमतें गिरती हैं।
- रसद और विनियामक बाधाएँ: व्यापारियों के माध्यम से निर्यात का समन्वय करना और निर्यात कोटा का अनुपालन सुनिश्चित करना परिचालन संबंधी चुनौतियाँ पैदा कर सकता है।

निष्कर्ष:

- चीनी निर्यात की अनुमति देने का कदम चीनी उद्योग, किसानों और श्रमिकों को समर्थन देने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण है - लेकिन घरेलू उपलब्धता और कीमतों पर नकारात्मक परिणामों से बचने के लिए सावधानीपूर्वक निगरानी की आवश्यकता है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: चीनी निर्यात पर प्रतिबंध आंशिक रूप से हटाने के केंद्र सरकार के फैसले के संभावित लाभों और चुनौतियों की जांच करें। इस कदम से भारत के चीनी उद्योग और किसानों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? (150 Words /10 marks)

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पटना में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान बैठकों की संख्या में गिरावट और विधानमंडलों की मर्यादा पर चिंता व्यक्त की।

- उन्होंने राजनीतिक दलों से विधायकों की गरिमा बनाए रखने, संसद को मजबूत करने और सार्थक चर्चा को प्रोत्साहित करने के लिए आंतरिक आचार संहिता स्थापित करने का आग्रह किया।

Birla urges parties to devise internal code for members

The Hindu Bureau
PATNA/DELHI

Expressing concern over the decline in number of sittings and decorum of legislatures, Lok Sabha Speaker Om Birla on Monday urged the political parties to devise an internal code of conduct for members' behaviour in the House.

He was speaking at the inaugural function of the 85th All India Presiding Of-

ficers Conference in Patna. Legislatures, Mr. Birla said, were a platform for debates and the legislators were expected to fulfil the hopes and aspirations of the people. People's representatives should follow constitutional propriety and must respect parliamentary traditions while expressing their viewpoint, he added.

"It is our collective responsibility to strengthen the Parliament and other



Om Birla

institutions; then only people will get maximum benefit. The House should be

saved from the repeated adjournments and there should be meaningful discussion. All members should maintain the dignity of the House," he said.

Role of House panels

Mr. Birla said the role of parliamentary standing committees should be increased as they worked like a mini-Parliament and had huge responsibility.

The Speaker added that empowering the commit-

tees would put pressure on the government and a better outcome would be visible.

The event was organised in the Bihar Assembly after a gap of 43 years.

The Lok Sabha Speaker said it was the duty of the presiding officers to run the House keeping the constitutional values and work towards setting a good example for strengthening the democratic institution.

The conference was at-

tended by Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh, Bihar Assembly Speaker Nand Kishore Yadav and presiding officers of State legislative bodies from across the country.

During the two-day conference, the presiding officers will brainstorm on the "75th Anniversary of Constitution: Contribution of Parliament and State legislative bodies in strengthening constitutional values.

आंतरिक आचार संहिता की आवश्यकता:

- यह सदन की कार्यवाही को व्यवस्थित बनाए रखता है और विधायी कार्य के लिए पेशेवर माहौल बनाए रखता है।
- यह विघटनकारी व्यवहार को रोकता है और सार्थक बहस को प्रोत्साहित करता है, जिससे चर्चाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है।
- यह सुनिश्चित करके लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि संवैधानिक और संसदीय परंपराओं का सम्मान करें।

लाभ:

- अच्छी तरह से लागू की गई आचार संहिता रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देती है और सत्रों के दौरान संघर्ष को कम करती है।
- यह स्वीकार्य व्यवहार पर स्पष्टता प्रदान करती है, जिससे अनियंत्रित घटनाओं और बार-बार स्थगन को रोका जा सकता है।
- सदन विधायी कार्य पर केंद्रित रहता है, जिससे सत्रों की दक्षता और उत्पादकता में सुधार होता है।
- विधायकों को अपने कर्तव्यों को जिम्मेदारी से पूरा करने और अन्य सदस्यों की भूमिकाओं और विचारों का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- आचार संहिता पार्टी लाइनों के पार सहयोग को बढ़ा सकती है, जिससे शासन के लिए अधिक सहयोगी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है।

चुनौतियाँ:

- राजनीतिक दलों को अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं और एजेंडों के कारण कार्यान्वयन में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

Daily News Analysis

- ▶ ऐसे सदस्यों का प्रतिरोध जो कोड को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या राजनीतिक रणनीति को सीमित करने के रूप में देख सकते हैं।
- ▶ विभिन्न पृष्ठभूमियों और राज्यों के विधायकों के विविध समूह द्वारा संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- ▶ जड़ जमाए हुए पक्षपातपूर्ण व्यवहार और सुधारों को अपनाने में अनिच्छा पर काबू पाना।

आगे की राह:

- ▶ राजनीतिक दलों को एक आचार संहिता तैयार करने के लिए रचनात्मक संवाद में शामिल होना चाहिए जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ संरेखित हो और संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करे।
- ▶ संहिता को लागू करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पीठासीन अधिकारियों को सशक्त बनाना।
- ▶ विधायकों के लिए शिष्टाचार बनाए रखने के महत्व के बारे में प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारतीय संसद में विधायकों के लिए आंतरिक आचार संहिता की आवश्यकता की जांच करें। ऐसी संहिता को लागू करने के संभावित लाभ और चुनौतियाँ क्या हैं, और यह लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को कैसे मजबूत कर सकती है? (250 Words /15 marks)



भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के अध्ययन ने 268 विमुक्त, अर्ध-खानाबदोश और खानाबदोश जनजातियों को वर्गीकृत किया है, तथा 179 को एससी, एसटी और ओबीसी सूचियों में शामिल करने की सिफारिश की है।

Study categorises 268 tribes, moots inclusion of 179 communities on SC, ST, and OBC lists

Abhinay Lakshman
NEW DELHI

In one of the largest ethnographic studies of its kind, the Anthropological Survey of India (AnSI) and Tribal Research Institutes (TRIs) across the country have, for the first time, comprehensively categorised 268 denotified, seminomadic, and nomadic tribes that previous commissions believed had never been classified.

The three-year-long study commissioned by a NITI Aayog panel has recommended the inclusion of 179 of these communities on Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes (Central) lists of 26 States and Union Territories. At least 85 of them are being recommended as fresh additions to these lists.

Among the fresh additions, 46 communities have been recommended for OBC status, 29 for SC status, and 10 for ST status. The greatest number of fresh additions were re-



Inclusive approach: People waiting for caste certificates in Sangareddy district, Telangana. FILE PHOTO

commended for Uttar Pradesh (19), followed by Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, and Rajasthan at eight each.

Apart from the fresh additions, the study recommended correcting the categorisation of nine communities, and found that many of the 268 communities had already been categorised, albeit partially, either in State lists or mentioned in Central lists but only of some States.

Top officials of the Social Justice Ministry told *The Hindu* that the report was “pending” with the NI-

TI Aayog panel, which was “scrutinising” the AnSI and TRIs’ findings. But the Union Ministry of Tribal Affairs revealed in a Parliament reply last year that the Social Justice Ministry had received this report in August 2023.

Groups not traceable

The study also concluded that 63 communities (more than 20%) studied were “not traceable” anymore.

Multiple researchers associated with the study explained that ‘not traceable’ was a classification for communities that had like-

ly assimilated into larger communities, changed their names, or migrated to other States/Union Territories.

This report’s recommendations to add entries to the SC, ST, OBC lists, which will consequently swell their populations, comes as uncertainty grows over the next Census and whether caste will be enumerated in it, with the clamour for increasing quota percentages to match with latest proportions only growing in the absence of a population count.

Significantly, modalities for inclusion and exclusion set down by the Government of India mandate that any such proposal must originate with the State/Union Territory governments, only after which can approvals be sought from the Office of the Registrar General of India and the National Commissions for SC, ST, or OBC respectively, before the government can think of bringing legislation for it.

While the Social Justice

Ministry waits for the “finalised” report from the NITI Aayog panel, sources told *The Hindu* that voices have now emerged within the Development and Welfare Board for DNT, NT, SNT communities (DWBDNC) that are calling into question the premise of classifying DNTs, NTs and SNTs as SC, ST, and OBC.

Their argument is that being a DNT, NT or SNT, adds a layer of discrimination to their lives, because of which the only fair classification would be to create a quota category just for these communities – either a separate vertical or a sub-quota for them within each category.

The ethnographic study was started by the Anthropological Survey of India in February 2020, according to replies to Right to Information Act requests.

The study was commissioned by a special panel constituted by the Prime Minister’s Office in February 2019.

समाचार का विश्लेषण:

- भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण (एएनएसआई) और जनजातीय शोध संस्थानों (टीआरआई) ने तीन साल लंबा नृवंशविज्ञान अध्ययन किया।
- अध्ययन में 268 विमुक्त, अर्ध-खानाबदोश और खानाबदोश जनजातियों को वर्गीकृत किया गया, जिन्हें पहले वर्गीकृत नहीं किया गया था, जिनमें बंजारा, गोंड, कंजर, धनगर, सहरिया और राजपूत जैसी जनजातियाँ शामिल हैं।

Daily News Analysis

- इनमें से 46 समुदायों को ओबीसी का दर्जा देने की सिफारिश की गई है, जिसमें बंजारा और गोंड शामिल हैं, 29 को एससी का दर्जा देने की सिफारिश की गई है, जिसमें सहरिया और धनगर शामिल हैं, और 10 को एसटी का दर्जा देने की सिफारिश की गई है, जिसमें गोंड और कंजर शामिल हैं।
- उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नए समुदाय शामिल किए गए, जिसमें सहरिया, धनगर और कंजर जैसे 19 समुदायों को शामिल करने की सिफारिश की गई।
- 63 समुदायों को "पता नहीं लगाने योग्य" के रूप में वर्गीकृत किया गया, जो संभावित आत्मसात या प्रवास का संकेत देता है।
- अध्ययन के निष्कर्ष नीति आयोग पैनल द्वारा जांच के अधीन हैं।
- यह रिपोर्ट जाति-आधारित कोटा और अगली जनगणना में इन समुदायों को शामिल करने पर बहस को प्रभावित कर सकती है।

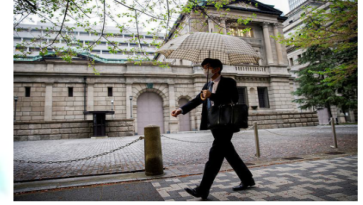


बैंक ऑफ जापान (BoJ) ने ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला किया है। दरों में बढ़ोतरी से अल्पकालिक उधारी लागत मौजूदा 0.25% से बढ़कर 0.5% हो जाएगी।

बैंक ऑफ जापान ने दरें बढ़ाने का फैसला क्यों किया?

- बैंक ऑफ जापान (BoJ) ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए दरें बढ़ाने का फैसला किया।
- मुद्रास्फीति पिछले तीन वर्षों से BoJ के 2% लक्ष्य से अधिक रही है।
- कमजोर येन ने आयात लागत को ऊंचा रखा है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ रही है।
- जापान में वेतन वृद्धि का दायरा बढ़ने से आर्थिक विकास को बनाए रखने में मदद मिल है।
- यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए भी है कि जापान अपने मुद्रास्फीति लक्ष्य को स्थायी रूप से प्राप्त करने के लिए सही रास्ते पर बना रहे।
- दर वृद्धि से अर्थव्यवस्था को संतुलित करने में मदद मिलेगी, जिससे अधिक गर्मी या ठहराव से बचा जा सकेगा।

BoJ set to raise rates to highest in 17 years



Costly step: This would lift short-term borrowing costs to levels unseen since 2008 global financial crisis. REUTERS

Reuters
TOKYO

The Bank of Japan (BoJ) is expected to raise interest rates on Friday barring any market shocks when U.S. President-elect Donald Trump takes office, a move that would lift short-term borrowing costs to levels unseen since the 2008 global financial crisis. A tightening in policy would underscore the central bank's resolve to steadily push up interest rates, now at 0.25%, to near 1% – a level analysts see as neither cooling nor overheating Japan's economy.

At the two-day meeting ending on Friday, the BOJ is likely to raise its short-term policy rate to 0.5% unless Mr. Trump's inaugural speech and executive orders upend financial markets, sources have told Reuters.

In a quarterly outlook report, the board is also expected to raise its price forecasts on growing prospects that broadening wage gains will keep Japan on track to sustainably hit the bank's 2% inflation target. A hike by the BOJ would be the first since July last year when the move, coupled with weak U.S. jobs data, shocked traders and triggered a rout in global markets in early August.

Treading with caution

Keen to avoid a recurrence, the BOJ has carefully prepared markets with clear signals by Governor Kazuo Ueda and his deputy last week that a rate hike was on the cards. The remarks caused the yen to rebound as markets priced in a roughly 80% chance of a rate increase on Friday.

There were also hints of near-term action last month. While the BoJ held off raising rates at the December 18-19 meeting, hawkish board member Naoki Tamura proposed pushing up rates. Some of his colleagues also saw conditions fall into place for an imminent rate hike, minutes of the meeting showed.

With a policy tightening this week seen as a near certainty, market attention is shifting to Mr. Ueda's post-meeting briefing for clues on the timing and pace of subsequent increases.

As inflation has exceeded the BoJ's 2% target for nearly three years and the weak yen has kept import costs elevated, Mr. Ueda is likely to stress policymakers' resolve to continue raising interest rates. But there is a good reason to tread cautiously. While the International Monetary Fund raised its forecast for global growth in 2025, Mr. Trump's policies risk destabilising markets and stoking uncertainty about the outlook for Japan's export-reliant economy.

Domestic political uncertainty could heighten, too, as Prime Minister Shigeru Ishiba's minority coalition may struggle to pass Budget through Parliament and win an upper house election scheduled in July.

The economic damage caused by past ill-fated rate hikes also haunt BOJ policymakers. The BoJ ended quantitative easing in 2006 and pushed short-term rates to 0.5% in 2007, moves that triggered a storm of political criticism as delaying an end to deflation.

The BoJ cut rates from 0.5% to 0.3% in October 2008, then to 0.1% in December of that year, as the global financial crisis pushed Japan into recession. Since then, various unconventional steps have kept borrowing costs stuck near zero.

रही

In News : WEF Annual Meeting

WEF की वार्षिक बैठक वर्तमान में 20 से 24 जनवरी, 2025 तक स्विट्जरलैंड के दावोस में हो रही है।



समाचार का विश्लेषण:

- **WEF का उद्देश्य और आरंभ**
- विश्व आर्थिक मंच की स्थापना जर्मन प्रोफेसर क्लॉस श्वाब ने 1971 में की थी, जिसे मूल रूप से यूरोपीय प्रबंधन मंच के रूप में जाना जाता था।
- व्यापार नीति के प्रोफेसर श्वाब ने "हितधारक पूंजीवाद" की अवधारणा पेश की, जिसमें व्यवसायों को केवल शेयरधारकों के बजाय सभी हितधारकों के हितों पर विचार करके दीर्घकालिक मूल्य बनाने की वकालत की गई।
- इस दृष्टिकोण ने WEF को वैश्विक नेताओं के एक साथ आने और आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मंच के रूप में विकसित किया।

WEF का विकास और गतिविधियाँ

- शुरू में यूरोपीय प्रबंधन प्रथाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने वाले WEF ने 1973 में महत्वपूर्ण वैश्विक घटनाओं, जैसे ब्रेटन वुड्स प्रणाली के पतन और अरब-इज़राइल युद्ध के बाद अपना दायरा बदल दिया।
- 1975 तक, फ़ोरम ने दुनिया की अग्रणी 1,000 कंपनियों को शामिल करने के लिए अपनी सदस्यता का विस्तार किया।
- पिछले कुछ वर्षों में, यह एआई, भू-राजनीतिक जोखिम और जलवायु परिवर्तन सहित महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों से निपटने के लिए एक प्रमुख स्थल बन गया है, और इसमें 500 से अधिक सत्र होते हैं, जहाँ व्यापारिक नेताओं, राजनेताओं और विशेषज्ञों सहित हज़ारों प्रतिभागी समाधानों पर सहयोग करते हैं।

WEF का वित्तपोषण और स्थान

- WEF को बड़े पैमाने पर वैश्विक निगमों द्वारा वित्तपोषित किया जाता है, जिनका वार्षिक राजस्व \$5 बिलियन से अधिक है।

- स्विस् के शांत शहर दावोस को बैठक स्थल के रूप में चुना जाना इसके शांत और केंद्रित वातावरण से प्रेरित है, जो प्रभावी चर्चाओं को बढ़ावा देने में मदद करता है।
- इस स्थान ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ऐतिहासिक क्षणों को भी देखा है, जैसे कि उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच पहली बैठकें और दक्षिण अफ्रीकी राजनीतिक संक्रमण के दौरान महत्वपूर्ण बातचीत।

ऐतिहासिक महत्व और कूटनीतिक प्रभाव

- अपने पूरे इतिहास में, WEF अभूतपूर्व कूटनीतिक जुड़ावों का स्थल रहा है।
- इसने दक्षिण अफ्रीका के मेल-मिलाप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें 1992 में नेल्सन मंडेला, एफ.डब्ल्यू. डी क्लार्क और मैंगोसुथु बुथेलेजी की पहली संयुक्त उपस्थिति भी शामिल थी।
- इसके अतिरिक्त, WEF ने G20 की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिस पर पहली बार 1998 की बैठक में चर्चा की गई थी, और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट और वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट जैसी पहलों के माध्यम से वैश्विक नीति निर्णयों को प्रभावित करना जारी रखा है।

UGC's draft regulation has serious constitutional issues

The draft regulation by the University Grants Commission (UGC) on the selection and appointment of vice chancellors of universities has evoked protests by non-Bharatiya Janata Party-headed State governments. Their main objection against this regulation is that it constitutes a violation of the federal principles enshrined in the Constitution of India. The State governments concerned have demanded its withdrawal.

The UGC has sought to amend Regulation 2010 that relates to the selection and appointment of vice chancellors by widening the area of selection. Under the existing regulations, a vice chancellor can be selected only from among academicians who have a minimum experience of 10 years as professor. Through this amendment, the UGC declares that professionals with 10-plus years of experience in industry, public administration or public policy, shall also be considered.

The draft regulation raises serious constitutional issues which need to be examined by separating the political context of protest and a possible political reaction from the UGC or the party in power.

The objective of the UGC Act

The University Grants Commission Act, 1956 was enacted by Parliament to make provision for "the co-ordination and determination of standards in Universities and for that purpose, to establish the University Grants Commission". The Act, therefore, mandates the UGC to take all steps as it thinks fit for the promotion and the coordination of university education, and for the determination and maintenance of standards of teaching, examination and research in universities. For performing these functions the UGC can allocate funds to the universities essentially for the maintenance and development of the universities, recommend measures necessary for the improvement of university education, advise the Union or State governments on the allocation of grants to universities for any general or specific purpose, collect information on all matters relating to university education in India and other countries and make them available to any university, regulation of fees.....

Section 26 of the UGC Act empowers the UGC to make regulations for implementing the mandate of the Act. But it is made clear in this section that these regulations need to be consistent with the Act and the rules made there under. The most important among these regulations relate to defining the qualifications required of a person to be appointed to the teaching staff in a university, the minimum standards of instructions for the grant of any



P.D.T. Achary

is former Secretary General, Lok Sabha

degree by a university, and regulating the maintenance of standards and the coordination of work or facilities in universities.

It is not the job of the UGC

The crucial point that needs to be considered here is whether the regulation made by the UGC in respect of the selection, qualification and appointment of vice chancellor is consistent with the provisions of the UGC Act. As a matter of fact, the Act does not contain any provisions relating to the selection and the appointment of vice chancellors. The fundamental objective of the Act is to determine standards in universities and the promotion and the coordination of university education. To lay down the standards of teaching and to prescribe the qualifications of teaching staff whose job is to give instructions, is the main function of the UGC – which it does by making periodic regulations. But the problem arises when this statutory body begins to regulate an area which is not a part of the parent Act. Rules, and regulations are technically called subordinate legislation. The subordinate legislation can be made only in consonance with the provisions in the Act. If the regulation goes outside the scope of the Act, it will be *ultra vires* the Act, and hence invalid.

A close reading of the Act would show that it was not meant to prescribe the qualifications or mode of selection of vice chancellors. All universities, whether under the Union or the States, are established under a statute made by the respective legislature. Therefore, it is the legislature which prescribes the qualifications, mode of selection, and conditions of service of vice chancellors. It is not the job of the UGC. The selection and the appointment of vice chancellors cannot be considered to be an exercise connected with maintaining the standards of education or promotion and coordination of university education. The Bombay High Court in *Suresh Patilkhede vs The Chancellor Universities of Maharashtra and Others* (2011) corroborates this view in the following words "we are of the view that qualifications and method of appointment of Pro-Chancellor and Vice Chancellor of the University cannot be treated as satisfying the 'direct impact' test [on the standards of education]". Therefore, it is safe to assume that under Section 26 of the UGC Act, the UGC has no mandate to make any regulation in respect of the selection and the appointment of vice chancellors.

An interesting constitutional question which arises in the context of the UGC's regulations is whether a regulation can over-ride an Act passed by a State legislature. This question came up in the context of the termination of the appointment

The problem arises when the UGC begins to regulate an area which is not a part of the parent Act – namely the selection and the appointment of university vice chancellors

of some vice chancellors in the past. The Bombay High Court in the *Suresh Patilkhede case (supra)* took the view that "Regulation 7.3.0 of UGC Regulations, 2010 being a subordinate legislation under an Act of Parliament cannot override plenary legislation enacted by the State Legislature...." However, the Supreme Court of India, in *Kalyani Mathivanan vs K.V. Jeyaraj and Ors (AIR 2015 SC1875 para 22)* overruled it by holding "we hold that the U.G.C. Regulations through a subordinate legislation has binding effect on the Universities to which it applies...." The reason given by the Court for reaching this conclusion is that "it is only when both the Houses of the Parliament approve the regulation, the same can be given effect". It may be clarified here that Parliament does not formally approve any rule or regulation laid in the House. It can only amend a rule which has already come into effect before it is so laid; if Parliament amends the rule, it will, thereafter, be effective in the amended form. With due respect to their lordships, the observation of the Court does not correctly reflect the parliamentary procedure relating to the laying down of rules and regulations in the Houses of Parliament.

The question whether the UGC regulations override a State law can be answered only in terms of Article 254 of the Constitution which deals with repugnancy. Under this Article, if a State law is repugnant to the central law, the State law, to the extent of repugnancy, be void. But is a regulation made by the UGC, a central law within the meaning of Article 254? Clause (2) of this Article says that if the law made by the legislature of a state has been reserved for the consideration of the President and has received his ascent, it shall prevail in the State. In this clause the word 'law' simply means the Bill passed by the legislature and sent to the President. It does not include the rules and regulations which are framed only after ascent is received. So, what overrides a State law is a Bill passed by both Houses of Parliament and assented to by the President, and certainly not the subordinate legislation.

A key ruling

In any case, the Court made a significant ruling on the question of mandatory application of Regulation 7.3.0 of the UGC relating to the selection and appointment of vice chancellors in the *Kalyani Mathivanan case (supra)* it says: "However, the finding of the Bombay High Court that Regulation 7.3.0 has to be treated as recommendatory in nature is upheld in so far as it relates to Universities and Colleges under the State Legislation." This ruling may perhaps help resolve the present controversy.

GS Paper 02 : शासन

UPSC Mains Practice Question: भारतीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मसौदा विनियमन के संवैधानिक और संघीय निहितार्थों पर चर्चा करें। (150 Words /10 marks)

संदर्भ :

- ▶ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों (VC) के चयन और नियुक्ति पर एक मसौदा विनियमन प्रस्तावित किया है।
- ▶ गैर-भाजपा नेतृत्व वाली राज्य सरकारें इस विनियमन का विरोध करती हैं, उनका दावा है कि यह संविधान के संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

UGC द्वारा प्रस्तावित संशोधन

- ▶ संशोधन पात्रता मानदंड को व्यापक बनाकर VC नियुक्तियों के संबंध में विनियमन 2010 को संशोधित करने का प्रयास करता है।
- ▶ पहले, केवल प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले शिक्षाविद ही पात्र थे।
- ▶ नए प्रस्ताव में उद्योग, लोक प्रशासन या सार्वजनिक नीति में 10 या अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाले पेशेवर शामिल हैं।

UGC अधिनियम, 1956 का उद्देश्य

- ▶ UGC अधिनियम विश्वविद्यालयों में मानकों का समन्वय और निर्धारण करने के लिए अधिनियमित किया गया था। UGC विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देता है और शिक्षण, अनुसंधान और परीक्षाओं के मानकों को बनाए रखता है।
- ▶ अधिनियम UGC को निम्नलिखित की अनुमति देता है: विश्वविद्यालयों के रखरखाव और विकास के लिए धन आवंटित करना।
- ▶ शिक्षा में सुधार के उपायों की सिफारिश करना। विश्वविद्यालयों को अनुदान पर सरकारों को सलाह देना। विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित जानकारी एकत्र करना और साझा करना।

यूजीसी की भूमिका और सीमाएँ

- ▶ यूजीसी अधिनियम की धारा 26 यूजीसी को नियम बनाने की अनुमति देती है, लेकिन इन्हें अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए।

- यह अधिनियम कुलपतियों के चयन या नियुक्ति को कवर नहीं करता है, क्योंकि इनका निर्धारण संबंधित विधानसभाओं द्वारा पारित कानूनों द्वारा किया जाता है।
- वीसी का चयन और नियुक्ति सीधे तौर पर शैक्षिक मानकों के रखरखाव को प्रभावित नहीं करती है, जैसा कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सुरेश पाटिलखेड़े बनाम द चांसलर यूनिवर्सिटीज ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स (2011) में पुष्टि की है।
- इसलिए, कुलपति नियुक्तियों पर यूजीसी का विनियमन इसके अधिकार से परे हो सकता है और इसे अमान्य घोषित किया जा सकता है।

नियम बनाम राज्य कानून

- एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठता है: क्या यूजीसी विनियमन राज्य कानूनों को ओवरराइड कर सकते हैं?
- बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यूजीसी विनियमन राज्य कानूनों को ओवरराइड नहीं कर सकते क्योंकि वे अधीनस्थ कानून हैं।
- हालांकि, कल्याणी मथिवनन बनाम के.वी. जयराज और अन्य (2015) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यूजीसी विनियमन विश्वविद्यालयों पर बाध्यकारी अधिकार रखते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विनियमों के प्रभावी होने के लिए संसदीय अनुमोदन आवश्यक है, लेकिन संसदीय प्रक्रिया की इस व्याख्या पर सवाल उठाए गए हैं।

संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से समाधान

- संविधान का अनुच्छेद 254 राज्य और केंद्रीय कानूनों के बीच संघर्षों को संबोधित करता है।
- केवल केंद्रीय कानून (संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत) ही राज्य के कानूनों को रद्द कर सकते हैं।
- अधीनस्थ कानून के रूप में यूजीसी विनियम, इस अनुच्छेद के तहत केंद्रीय कानून के रूप में योग्य नहीं हैं।

निष्कर्ष

- यूजीसी का मसौदा विनियमन यूजीसी अधिनियम के तहत अपने अधिदेश से आगे निकल जाता है, जिससे संवैधानिक चिंताएँ पैदा होती हैं।
- यह संघीय सिद्धांतों और राज्य स्वायत्तता का सम्मान करते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।